राज्य में हत्या प्रकरणों में 25 व लूट में 50 प्रतिशत कमी आई- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने ''विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था'' विषय पर पुलिस सम्मेलन को संबोधित किया

जयपुर, 8 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सुदृढ़ कानून व्यवस्था की निर्णायक भूमिका है। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता में त्वरित न्याय की अवधारणा से लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है।

गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में 'विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023 के मुकाबले अपराधों में 15 प्रतिशत, हत्या के प्रकरणों में 25 प्रतिशत, लूट के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, महिला अत्याचार में 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार में 28 प्रतिशत की कमी आई है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को अपने कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने चाहिए।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में ''विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था'' विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण के नवाचारों ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है और भारत सरकार के उपक्रम ''क्षमता संवर्धन आयोग'' द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा इन पर पूरी तरह अंकुश लगाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रही है और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण में किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण के महत्व को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को अपने कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने चाहिए। 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले पुलिस अधिकारियों को एक-एक पुलिस स्टेशन को गोद लेना चाहिए।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग के लिए समर्पित भाव से कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ई-विज़िटर्स पोर्टल एवं ई-जीरो एफआईआर का शुभारम्भ एवं राजस्थान पुलिस प्राथमिकता-2026 पुस्तिका का विमोचन किया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी संजीव कुमार नर्जरी सहित, पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

बंगलादेश ने भारत में वीज़ा अनुभाग बंद किया

ढाका, 08 जनवरी। बंगलादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत में अपने तीन मिशनों के वीज़ा अनुभाग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

तौहीद हुसैन ने मीडिया से कहा, ''मैंने अपने तीन मिशनों से कहा है कि वे फिलहाल अपने वीज़ा अनुभाग बंद रखें। यह सुरक्षा का मामला है।'' उन्होंने हालांकि मिशनों के नाम नहीं बताए, लेकिन यूएनबी के अनुसार, बंगलादेश ने नयी दिल्ली में बंगलादेश उच्चायोग, कोलकाता में उप उच्चायोग और अगरतला में सहायक उच्चायोग के वीज़ा अनुभाग बंद कर दिए हैं, जबकि चेन्नई और मुंबई में बंगलादेश मिशनों के वीज़ा अनुभाग कार्यरत हैं।

- **बंगलादेश के अनुसार यह सुरक्षा के कारण किया गया है।**

ऑब्ज़र्वर बंगलादेश के अनुसार, कोलकाता उप उच्चायोग में वीज़ा सेवाओं का निलंबन बुधवार से प्रभावी हुआ। इस फैसले के तहत भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीज़ा सेवाएं, वाणिज्यिक और वर्क वीज़ा को छोड़कर रोक दी गई हैं। वाणिज्यिक और वर्क वीज़ा को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए वाणिज्य दूतावास और वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।

तुर्कमान गेट मस्जिद के पास पथराव में 30 आरोपियों की पहचान

तुर्कमान गेट के पास फैज़ ए- इलाही मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने गई नगर निगम टीम पर स्थानीय लोगों ने पत्थर बरसाए थे

नई दिल्ली, 08 जनवरी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास नगर निगम के अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई हिंसा में शामिल 30 लोगों की पहचान कर ली है। यह पहचान सीसीटीवी फुटेज, पुलिसकर्मियों के बॉडी-वॉर्न कैमरे की रिकॉर्डिंग और इलाके के वायरल वीडियो के आधार पर की गई है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही समन भेजा जाएगा, क्योंकि आरोप है कि हिंसा शुरू होने से पहले वे घटनास्थल पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार, सीनियर अधिकारियों ने सांसद से घटनास्थल से दूर रहने का अनुरोध किया था, लेकिन घटना से पहले वे उस इलाके के पास ही रहे। आरोपियों की पहचान करने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं, और पहचाने गए लोगों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी की जा रही है।

एफआईआर की कॉपी में घटनाओं का पूरा क्रम दर्ज है, जिसमें अतिक्रमण वाली जमीन पर पुलिस की बैरिकेडिंग से लेकर एक दर्जन स्थानीय लोगों द्वारा भड़काऊ नारे लगाने और फिर पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने तक की बातें शामिल हैं। पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह तोड़फोड़ अभियान सिर्फ अवैध निर्माणों और अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीन को खाली कराने तक सीमित है और पास की मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। एफआईआर के अनुसार, करीब 12:40 बजे, जब पुलिसकर्मियों ने इलाके में बैरिकेडिंग शुरू की, ठीक उसी समय 30-35 लोगों का एक समूह मौके पर एकत्र हो गया और नारे लगाने लगा तथा पुलिस को नाकाबंदी करने से रोकने लगा।

- **इस मामले में पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से भी पूछताछ करेगी। आरोप है कि हिंसा शुरु होने से पहले वे वहीं थे।**

उपद्रवी तत्वों से कहा गया कि वे मौके पर इकट्ठा न हों, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 (जो उपद्रव या संभावित खतरे के मामलों में लागू होती है) लागू थी और उन्हें जल्दी से तितर-बितर हो जाना चाहिए था, लेकिन भीड़ नरम पड़ने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गई। भीड़ ने नारेबाजी तेज कर दी और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने और भीड़ द्वारा बैरिकेड्स को नुकसान पहुंचाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिससे ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों पर सीधे हमले को लेकर नेटिजन्स के एक वर्ग में गुस्सा देखा गया। एफआईआर में कहा गया कि एक प्रदर्शनकारी ने लाउडस्पीकर छीन लिया और उसे तोड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को रोका और उन पर हमला किया, बल्कि लाउडस्पीकर-बैरिकेड्स भी तोड़े और पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला किया। इस हमले में एसएचओ सहित, कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए और बाद में उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अतिरिक्त बल बुलाए जाने के बाद ही हिंसक प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला गया और धार्मिक ढांचे के आसपास की अवैध संरचनाओं को गिरा दिया गया। एफआईआर में नामजद पांच आरोपियों की पहचान मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद आरिब, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद अदनान और मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है। ये सभी चांदनी महल इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

भारत ने रुसी तेल की खरीद में चुपचाप कमी की

इसकी भरपाई के लिए परमाणु सहयोग में भारी बढ़ोतरी की संभावना है

नयी दिल्ली, 08 जनवरी। पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका द्वारा रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी के मद्देनजर, भारतीय कंपनियों ने रूस से कच्चे तेल का आयात कम कर दिया है या पूरी तरह से रोक दिया है।

भारत ने हालांकि आधिकारिक रूप से कहा है कि उसे किसी भी स्त्रोत से कच्चे तेल की खरीद करने का अधिकार है, लेकिन उसने चुपचाप रूस से खरीद को कम कर दिया है, जबकि अमेरिका से आयात में वृद्धि हुई है। अधिकारियों ने कहा कि भारत रूस के साथ अपने रक्षा एवं परमाणु सहयोग का विस्तार कर रहा है और रूस को संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच तेल व्यापार में कमी आयी है।

- **भारत ने अधिकारिक रुप से कहा कि हमें किसी भी देश से तेल खरीदने का अधिकार है, पर ट्रंप की धमकियों के कारण तेल रिफाइनरियों को चुपचाप रुसी तेल खरीद बंद करने की सलाह दी गई है।**

सरकारी तेल रिफाइनरियों को चुपचाप रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति कम करने और गैर-प्रतिबंधित कंपनियों से अपनी खरीद सीमित करने की सलाह दी गई है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कहना है कि उसे पिछले तीन हफ्तों से कोई रूसी कच्चा तेल नहीं मिला है और न ही इस महीने मिलने की उम्मीद है। भारत ने किसी एक देश से तेल आयात को अपनी कुल कच्चे तेल की खरीद का 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रखने का नीतिगत निर्णय भी लिया है। यह कदम भू-राजनीतिक जोखिमों को सीमित करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के अपने दीर्घकालिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

जयपुर का न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रहा

जयपुर, 08 जनवरी। राजस्थान में शीतलहर एवं कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी हैं और पिछले 24 घंटों में 2.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सीकर सबसे सर्द स्थान रहा, जबकि सुबह कुछ स्थानों पर घने से अति घना कोहरा छाया रहा। वहीं आगामी दो-तीन दिनों में सर्दी के और बढ़ने की संभावना है।

- **अगले 2-3 दिन सर्दी और बढ़ने की संभावना।**

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में इस दौरान जैसलमेर भी 3.3 डिग्री सेल्सियस के साथ काफी ठंडा स्थान रहा जबकि राजधानी जयपुर में 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

पर्वतीय स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

विभाग के अनुसार, आगामी दो तीन दिन में उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में न्यूनतमत तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने एवं तापमान सामान्य से दो-चार डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज होने तथा शीतलहर चलने के आसार हैं।

दिल्ली में फ्लू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कुछ मरीजों में इन्फ्लुएंजा, जिसमें एच3एन2 भी शामिल है, पाया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि एक साथ कई तरह के श्वसन वायरस और यहां तक कि बाद में होने वाले बैक्टीरियल संक्रमण भी फैल रहे हो सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह फ्लू क्यों फैल रहा है और शुरुआती दौर में सही कदम उठाने से इसकी गंभीरता और फैलाव दोनों को कम किया जा सकता है।

मणिपाल हॉस्पिटल, द्वारका में संक्रामक रोग विभाग की प्रमुख और सलाहकार डॉ. अंकिता बैद्य का कहना है, ''यह अभी की बात नहीं है, लगभग एक महीने से चल रहा है। फ्लू के बहुत मामले सामने आ रहे हैं और सांस से जुड़ी कई बीमारियां देखी जा रही हैं। यह खासकर यात्रा करने वाले लोगों में ज्यादा है और सभी उम्र के लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं।''

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली के वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. अवि कुमार का भी कहना है कि कुछ मामलों में एच3एन2 जरूर है, लेकिन वही अकेला कारण नहीं है।

ममता अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दफ्तर से चुनावी रणनीति और दूसरी चीज़ों से जुड़ा डेटा ले जा रही थी, इसलिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ा। यह स्पष्ट रूप से एक राज्य की मुख्यमंत्री द्वारा अपनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके चल रही जांच में रूकावट डालना था। ई.डी. ने बाद में जोर देकर कहा कि ममता बनर्जी के आने से पहले जांच बिल्कुल ठीक और पेशेवर तरीके से चल रही थी। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचीं, अफरा-तफरी मच गई और जांच से जुड़े अहम सबूत ईडी अधिकारियों के सामने ही वहां से हटा लिए गए। अब देखना यह है कि ईडी और केन्द्र सरकार इस स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर यही काम किसी आम आदमी ने किया होता तो न्याय और जांच में रूकावट डालने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता। लेकिन ममता बनर्जी और उनके साथियों का मामला अलग ही है। साफ तौर पर कानून तोड़ने के बावजूद, उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं होती। एक मशहूर मामला यह भी है कि जब अभिषेक बनर्जी की पत्नी बैंकॉक से कोलकाता हवाई अड्डे पर भारी मात्रा में सोने के साथ पकड़ी गई थीं, तब राज्य पुलिस का दस्ता भेजकर उन्हें और सोने को वहां से छुड़ा लिया गया। उस मामले में भी आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।

सरमथुरा में खनन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विभाग का दल मौके पर पहुंचा। अवैध खनन रोकने के प्रयास के दौरान वनरक्षक जितेन्द्र सिंह के बाएं पैर पर ट्रैक्टर का टायर चढ़ गया।

इस घटना से वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। ट्रैक्टर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग का अन्य दल मौके पर पहुंचा। घायल जितेन्द्र सिंह को तत्काल सरमथुरा अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें करौली रेफर किया गया और फिर जयपुर भेजा गया। विभाग का एक दल उनके साथ जयपुर गया है। वनरक्षक जितेन्द्र सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि घायल वनरक्षक के होश में आने के बाद ही घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। यह घटना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई है।

लगातार नौवाँ बजट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिए संयुक्त रणनीतियाँ तैयार कर सकते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बुधवार की बैठक में संसद के कैलेंडर को अंतिम रूप दिया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कैलेंडर के अनुसार, बजट सत्र दो हिस्सों में आयोजित होगा: पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक। सीतारमण इस साल, लगातार नौवाँ बजट पेश करके, एक रिकॉर्ड बनाएंगी। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड सबसे अधिक, 10 बजट पेश करने का है, लेकिन ये दो चरणों में पेश किए गए थे: 1959 से 1964 और 1967 से 1969 के बीच। पी चिदंबरम ने नौ और प्रणब मुखर्जी ने आठ बजट विभिन्न प्रधानमंत्रियों के कार्यकालों में पेश किए थे।

अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग हुआ

वाशिंगटन, 08 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए देश को 66 वैश्विक संगठनों से अलग करने की घोषणा की है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकायों सहित, इन 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोगों से अब अमेरिका का कोई वास्ता नहीं है। आदेश के अनुसार, ये समूह अब अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की सेवा नहीं करते हैं। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रम्प का रुख बेहद स्पष्ट है कि इन संस्थानों को अमेरिकी जनता की मेहनत की कमाई भेजना अब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इसके बदले में देश को कुछ भी हासिल नहीं होता है। बयान के मुताबिक, अमेरिकी लोगों की कीमत पर विदेशी हितों को अरबों डॉलर का करदाताओं का पैसा देने का दौर अब खत्म हो गया है।

- **ट्रंप का मानना है कि ये संगठन अब अमेरिका के हितकर नहीं है।**

विदेश विभाग ने स्पष्ट किया है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की समीक्षा अभी जारी है और प्रशासन हर मामले के आधार पर भविष्य में अमेरिकी भागीदारी का मूल्यांकन करता रहेगा।

भर्ती परीक्षा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जरिए नकल कराई जा रही थी। इस संबंध में एसओजी थाने में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि फेरिश कुमार स्वयं अभ्यर्थी था और गैंग से मिलीभगत कर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कर रहा था। मामला दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया था। जिस पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। एसओजी ने आरोपी फेरिश कुमार (26) निवासी कालू जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक कुल 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

क्या लद्दाख में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक गंभीर सवाल पैदा होता है कि ऐसे यूट्यूबरों को इतनी जोखिम भरी और खतरनाक जगहों पर जाने की अनुमति आखिर दी ही क्यों जाती है, वह भी खतरनाक मौसम के दौरान?'' उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बार-बार ऐसे बचाव अभियानों से सशस्त्र बलों पर बेवजह दबाव पड़ सकता है। ''इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए और अत्यधिक जोखिम वाले मौसम में ऐसी मंजूरियों को सख्ती से रोक देना चाहिए, ताकि जान-माल का नुकसान न हो और हमारी सशस्त्र सेनाएं अनावश्यक रूप से परेशान न हों।''

'भर्ती प्रक्रिया के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रहे कई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल और साक्षात्कार तक पहुंचे थे। इसके बाद वे असफल हो गए थे। ऐसे में नियमानुसार एक बार चयन प्रक्रिया में शामिल होने पर उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। चयनित अभ्यर्थियों की ओर से यह भी कहा गया कि परीक्षा के कई विभिन्न चरण हुए थे, जिसके हर स्तर पर मिलीभगत साबित नहीं हुई है। इसके अलावा एसओजी, महाधिवक्ता और कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट सिर्फ सिफारिश मात्र थी। एकलपीठ में याचिकाकर्ताओं ने भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय होने से पूर्व ही याचिका दायर कर दी। इसके बावजूद एकलपीठ ने भर्ती को रद्द करने के संबंध में आदेश दे दिए।

अप्रेल में राज्यसभा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीट का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। सिंघवी एक वकील हैं और कांग्रेस नेतृत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे कई महत्वपूर्ण मामलों को संभाल रहे हैं।

तेलंगाना से दो सीटें खाली हो रही हैं। रिटायर होने वाले दूसरे व्यक्ति मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी अनिल यादव हैं, तो वे वहां से लौट सकते हैं या राजस्थान से आ सकते हैं।

एक और प्रमुख दावेदार पवन खेड़ा हैं, जो एआईसीसी मीडिया चेयरमैन हैं और जिन्हें अशोक गहलोत का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इस बार गहलोत खुद को ही प्राथमिकता दे रहे हैं।

पिछली बार खेड़ा हार गए थे और तब उन्होंने विनम्रता से कहा था कि, ''मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी।'' इस बार अपनी तपस्या के तहत विपश्यना पर गए थे, हाल ही में लौटे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यही उनका काम बना देगी।

नीरज डांगी राजस्थान से रिटायर हो रहे हैं। लोकप्रियता से दूर तथा शांत रहने वाले डांगी अशोक गहलोत की पसंद थे, लेकिन यह संभावना कम है कि उन्हें फिर से मौका मिलेगा, फिर भी एक प्रयास में कोई हर्ज नहीं है।

वरिष्ठ नेता सी. पी. जोशी भी काफी समय से दिल्ली में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से रिश्ते खराब होने के बाद, अब वे के. सी. वेणुगोपाल के जरिए प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें राहुल गांधी का प्रॉक्सी माना जाता है।

पवन गोदारा, एक स्थानीय जाट नेता हैं, और यदि पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा को हटाया जाता है, तो एक जाट को राज्यसभा में समायोजित किया जा सकता है।

हालांकि राज्यसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि राहुल गांधी की ''जय जगत'' कोर टीम का प्रत्येक सदस्य राज्यसभा के लिए जोर लगा रहा है, क्योंकि उनके पास राहुल गांधी का समर्थन है और राहुल उनकी बात सुनते हैं।

प्रवीण चक्रवर्ती और सचिन राव राजस्थान से जोर लगा रहे हैं, मीना कश्यप मध्य प्रदेश से, और अन्य कई लोग भी इस दौड़ में हैं।

डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा अंतर है और मुकाबला आने वाले हफ्तों में और भी दिलचस्प हो सकता है!!

वांगचुक केस में बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, वांगचुक के उस भाषण को दबा दिया गया जिसमें उन्होंने शांति की अपील की थी

नयी दिल्ली, 08 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत, लद्दाख स्थित सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विस्तार से सुनवाई की।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए वांगचुक के पक्ष में मौजूद सामग्री, विशेष रूप से शांति की अपील करने वाले भाषण को, हिरासत में लेने वाले अधिकारियों ने जानबूझकर दबा दिया।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले की पीठ ने वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर आज पूरी सुनवाई की, जिसमें लद्दाख में कथित रूप से हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद 26 सितंबर, 2025 को पारित हिरासत आदेश को चुनौती दी गई है।

- **वांगचुक के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने दायर की है।**

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता सिब्बल ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश दुर्भावना से प्रेरित था और अनुच्छेद 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि यह आदेश मुख्य रूप से बंदी प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए चार वीडियो पर आधारित था, जिनकी तारीखें 10 सितंबर, 11 सितंबर और 24 सितंबर थीं।

हालांकि, 29 सितंबर को हिरासत के कारणों की जानकारी दी गई थी, लेकिन हिरासत का आधार बनने वाले ये चार वीडियो बंदी को नहीं दिए गए। सिब्बल ने तर्क दिया कि यह स्थापित कानून है कि जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनकी जानकारी दिए बिना हिरासत में लेना संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है, जिससे हिरासत अवैध हो जाती है। सरकार की ओर से दावा किया गया कि सभी सामग्री उपलब्ध करा दी गई थी। लेकिन सिब्बल ने जोर देकर कहा कि इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 28 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद हिरासत के आधार प्रस्तुत किए गए, जो वैधानिक समय सीमा का स्पष्ट उल्लंघन है।

सिब्बल के अनुसार, 29 सितंबर को वांगचुक को अधूरे आधार पर केवल हिरासत आदेश ही दिए गए, जबकि चार महत्वपूर्ण वीडियो गायब थे। उन्होंने बताया कि अंततः जो उपलब्ध कराया गया वह केवल वीडियो लिंक था। हालांकि पांच अक्टूबर को एक लैपटॉप उपलब्ध कराया गया। सिब्बल ने तर्क दिया कि इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि पहले दी गई पेन ड्राइव में वे चार वीडियो मौजूद नहीं थे, जिन पर भरोसा किया जा रहा था। सिब्बल ने न्यायालय को बताया कि वांगचुक ने हिरासत से बार-बार पत्र लिखकर वीडियो न मिलने की शिकायत की और उनकी प्रतियां मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

अमेरिका हमेशा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों पर वेनेज़ुएला के बदहाल तेल इन्फ्रास्टक्चर को फिर से बनाने और इसके घटते उत्पादन को फिर से जीवित करने के लिए दबाव बना रहा है। ऊर्जा विभाग ने कहा कि अमेरिका वेनज़ुएला के तेल क्षेत्र पर से आंशिक रूप से प्रतिबंध भी हटा रहा है।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने मंगलवार शाम को कहा कि वेनेज़ुएला अपने तेल का 50 मिलियन बैरल तक अमेरिकी बिक्री के लिए सौंपेगा, जिसकी कीमत मौजूदा बाज़ार मूल्य के हिसाब से लगभग 2.8 बिलियन डॉलर है।

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने ''रूस प्रतिबंध विधेयक'' को मंजूर कर दिया है, जिसे रूस के व्यापारिक साझेदारों, जैसे भारत, चीन और ब्राज़ील को रूस के तेल खरीदने के लिए दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो एक प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ हैं, ने यह जानकारी दी।

यदि यह विधेयक पास होता है, तो ग्राहम-ब्लूमेंटल प्रतिबंध विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर 500 प्रतिशत तक शुल्क लगाने का अधिकार देगा, जो जानबूझकर रूसी तेल या यूरेनियम खरीदते हैं और ''रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन प्रदान करते हैं।'' यह कड़ा प्रतिबंध पैकेज मास्को को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के उद्देश्य से है, क्योंकि ट्रम्प प्रशासन रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करने की कोशिश कर रहा है।

ग्राहम ने कहा कि उन्होंने बुधवार को वाइट हाउस में ट्रम्प से मुलाकात की, जिसमें राष्ट्रपति ने इस विधेयक का समर्थन किया, जो महीनों से तैयार किया जा रहा था। वाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की।

ग्राहम ने कहा, ''यह समयानुकूल होगा, क्योंकि यूक्रेन तो शांति के लिए समझौते कर रहा है और पुतिन बस बातें कर रहे हैं, निदोर्षों को मार रहे हैं।

ग्राहम ने कहा कि अगले हफ्ते में मतदान हो सकता है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कैसे होगा। सीनेट अगले हफ्ते एक छोटे-से सरकारी फंडिंग पैकेज पर विचार करने वाली है, जिसे हाउस ने अभी विचार में लिया है, अगर हाउस इसे पास करता है। अगले हफ्ते के बाद सीनेट में मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे के अवसर पर अवकाश होगा।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908